an>

Title: Regarding employees of MTNL.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं व्यथित इसलिए हूं कि इसके पूर्व 10 अगस्त को मैंने यही जीरो ऑवर इसी सदन में बोला था, लेकिन उस समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ। एक अप्रैल, 1986 को पूर्व टेलीफोन डिपार्टमेंट से दिल्ली और मुम्बई को निकालकर महानगर टेलीफोन निगम बनाया गया। 1986 से लेकर 1998 तक उन कर्मचारियों को पता नहीं था कि हम कहां हैं। डीम्ड डैपुटेशन तो 1998 में अपनी एन.डी.ए. सरकार आई, उस समय सुषमा स्वराज जी हमारी मंत्री थीं, उन्होंने लुकिंग ऑफ्टर सिचुएशन कंडीशन में इन सब को एब्जोर्ब करने की अनुमति दे दी। अब समाविष्ट हुए, वेज एग्रीमेंट हुआ, फिर उसको लेकर 2000 में बी.एस.एन.एल. बना, पूर्वारित जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था। बी.एस.एन.एल. बनने के बाद भी तुरन्त सरकार ने उनको गवर्नमेंट की पैंशन दे दी। एम.टी.एन.एल. के कर्मचारियों को नहीं दी, फिर 12 वर्ष लड़े, फिर पैंशन 12 वर्ष के बाद में मिली। 1986 से 1998 और 1998 के फिर 12 वर्ष बाद मिली। अब पैंशन मिली।

हाल ही में उन्होंने एक नया निर्णय ले लिया। दोनों पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स आज घाटे में हैं। ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बी.एस.एन.एल. के एम्पलाइज़ को 68.8 से लेकर 78.2 डी.ए. दे दिया। अब एम.टी.एन.एल. के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर मैंने 10 अगस्त को बात की, किसी ने बात नहीं की, मतलब डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं कर रहा है। नोटिस भी दिया गया, जीरो ऑवर में यहां पर बात रखी गई, उसके बावजूद आज तक निर्णय नहीं हुआ। नोटिस में एम.टी.एन.एल. की सर्विस में भी सुधार के लिए भी मांग है। हमने सरकार से 10 हजार करोड़ रुपये मांगे हैं, ताकि हम सर्विस भी अच्छी दें, कम्पनी को भी प्रोफिट में लायें। हाल ही में हमने यहां एक बिल पास कर दिया और हाईकोर्ट के जजेज़ को पूर्वानुमान 2004 से लेकर तनख्वाह और पर्क्स सारे बढ़ाये, लेकिन यहां यह कम्पनी है, जो अपने लिए न्याय के लिए लड़ रही है, कर्मचारी 78.2 परसेंट डी.ए. मांग रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से, खास करके आपसे विनती करता हूं कि हम जीरो ऑवर में जिस विषय को रखते हैं, उस विषय पर उस डिपार्टमेंट के लोग ध्यान तो देते हैं कि नहीं। उसका जवाब भी नहीं आता और इसलिए मैं आज दोबारा आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारियों को 78.2 परसेंट डी.ए. दिया जाये और सरकार 10 हजार करोड़ रुपये की राशि उनको एक ही बार दे दे, क्योंकि इससे पहले बहुत पैसा डिवीडेंड के माध्यम से सरकार के पास गया है। क्योंकि वह एक ही कम्पनी थी और आज कम्पनी अपनी बुरी हालत में है। एक बार सरकार पैसा दे दे और कम्पनी उर्जित अवस्था प्राप्त करेगी, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं और मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,

श्री सदाशिव लोखंडे,

श्री विनायक भाऊराव राऊत,

श्री राहुल शेवाले,

श्री संजय हरिभाऊ जाधव,

श्री गजानन कीर्तिकर,

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे,

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे,

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और

श्री राजन विचारे को श्री अरविंद सावंत के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।